भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या - 47**
उत्तर देने की तारीख – 01/12/2025

## डिजिटल शिक्षा के लिए संसाधन

47. **श्री बाबू सिंह कुशवाहा:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कई सरकारी स्कूलों में अभी भी डिजिटल शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधनों, जैसे कंप्यूटर, स्मार्ट क्लास, इंटरनेट कनेक्शन और प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव है, जिससे छात्र आधुनिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों के विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए कोई विशेष राष्ट्रीय योजना आरंभ की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने पर विचार कर रही है कि प्रत्येक सरकारी स्कूल डिजिटल कक्षाओं, ई-लर्निंग सामग्री और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों से युक्त हो ताकि सभी बच्चे एक समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें; और
(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में अब तक उठाए गए प्रमुख कदमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री जयन्त चौधरी)**

(क) से (घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे छात्रों और शिक्षकों की मांगों को पूरा करने के लिए हर स्थान पर मौजूदा स्थिति के आधार पर कार्य करें ताकि उन्हें डिजिटल रूप से शिक्षण अधिगम के लिए आवश्यक डिजिटल पहुंच प्रदान की जा सके।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य बातों के साथ-साथ छठी से XII कक्षा वाले सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 'आईसीटी और डिजिटल पहल' के तहत गैर-आवर्ती/आवर्ती अनुदान निम्नलिखित दो विकल्पों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है:

**विकल्प I:** इस विकल्प के तहत, जिन स्कूलों ने पहले आईसीटी सुविधा का लाभ नहीं उठाया है, वे अपनी आवश्यकता और जरूरत के अनुसार या तो आईसीटी या स्मार्ट क्लासरूम का विकल्प चुन

सकते हैं। 700 से अधिक नामांकन के मामले में, एक अतिरिक्त आईसीटी प्रयोगशाला पर भी विचार किया जा सकता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास टैबलेट/लैपटॉप/नोटबुक/एकीकृत शिक्षण शिक्षण उपकरण और ओपन-सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ-साथ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रशिक्षण और संसाधन सहायता जैसे हार्डवेयर की खरीद के लिए छूट है।इसमें स्वीकृत स्कूलों की संख्या के लिए आनुपातिक आधार पर डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम और डीटीएच चैनलों के लिए सहायता  शामिल होगा।

**विकल्प II**: इस विकल्प के तहत, जिन स्कूलों ने पहले से ही आईसीटी सुविधा का लाभ उठाया है, वे योजना के मानदंडों के अनुसार स्मार्ट क्लासरूम/टैबलेट का लाभ उठा सकते हैं।

आज तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को 1,77,088 आईसीटी प्रयोगशालाएं और 1,76,728 स्मार्ट क्लासरूम स्वीकृत किए गए हैं। इसमें वर्ष 2024-25 में सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) को संतृप्त करने के लिए स्वीकृत 3,564 आईसीटी प्रयोगशालाएं और 3,655 स्मार्ट क्लासरूम शामिल हैं। इसमें 20,553 आईसीटी लैब और 29,910 स्मार्ट क्लासरूम भी शामिल हैं, जिन्हें 2025-26 में सभी कार्यात्मक माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम से परिपूर्ण करने के लिए स्वीकृत दी गई है।

यूडाइज़+ 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार, 5,93,615 सरकारी स्कूल इंटरनेट कनेक्शन से सुसज्जित हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने बजट 2025 में बीएसएनएल द्वारा चरणबद्ध तरीके से दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे में वृद्धि करने के लिए 'भारतनेट' परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के प्रावधान की घोषणा की है।

'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के हिस्से के रूप में पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल दिनांक 17 मई, 2020 को शुरू की गई थी, जिसके तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तत्वावधान में देश भर में शिक्षा के लिए मल्टी-मोड पहुंच को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत की जाती है।  राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मातृभाषा/स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन पहलों की प्रभावशीलता का उपयोग, निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए एनसीईआरटी के साथ सहयोग करते हैं।पीएम ई-विद्या में भारत सरकार में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों /स्वायत्त निकायों (एबी)/अन्य मंत्रालयों को आवंटित 200 डीटीएच टीवी चैनल और 400 रेडियो चैनल शामिल हैं ताकि वे कक्षा 1-12 के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में अपनी आवश्यकता के अनुसार पूरक शिक्षा प्रदान कर सकें।

ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल अवसंरचना (दीक्षा) सभी ग्रेडों के लिए क्यूआर कोडेड एनर्जेइज्ड पाठ्यपुस्तकों (ईटीबी) के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री प्रदान करने के लिए देश का एक राष्ट्र, एक डिजिटल मंच है। दीक्षा में एक भागीदार के रूप में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों /एबी ने बहुभाषावाद को सक्षम करते हुए मातृभाषा/ स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में 3.7 लाख से अधिक सामग्री तैयार की है और योगदान दिया है। कुल मिलाकर, छात्रों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों द्वारा दीक्षा पर 565.28 करोड़ शिक्षण सत्र पूरे किए गए हैं। हितधारकों के पास दीक्षा पर 450 से अधिक वर्चुअल लैब और 100 वर्चुअल स्किल लैब (हिंदी और अंग्रेजी में 50-50) तक पहुंच है।

समग्र शिक्षा के तहत, दीक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल शिक्षा के लिए शिक्षक क्षमता निर्माण में सहायता की जा रही है। विभाग ने दीक्षा पर एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में निष्ठा (नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट) को भी लागू किया है, जिसमें डिजिटल शिक्षाशास्त्र, आईसीटी उपकरणों के उपयोग और प्रौद्योगिकी-सक्षम शिक्षण पर मॉड्यूल शामिल हैं।इसके अलावा, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, डीआईईटी, बीआरसी और सीआरसी डिजिटल शिक्षा के लिए शिक्षकों की तैयारियों को सुदृढ़ करने के लिए संसाधन सामग्री, डिजिटल सामग्री, प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाओं का संचालन करते हैं।

*****